प्रेस विज्ञप्ति

12 नवंबर, 2015

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्न बयान दिए :–

''प्रधानमंत्री की यूके यात्रा और ललित मोदी का प्रत्यार्पण

''29 देशों की यात्रा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाईटेड किंगडम में है। पिछले सभी अनुभव ये बताते हैं कि विदेशों में उनकी यात्रा मात्र अपना प्रचार–प्रसार करने का तमाशा हैं, उम्मीद है कि इस बार की यात्रा के देश को कुछ ठोस लाभ मिलेंगे।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन में अपने समतुल्य के समक्ष भारतीय कानून के भगोड़े अपराधी ललित मोदी के प्रत्यार्पण का मुद्दा उठाएं और उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाएं।

प्रधानमंत्री को स्पष्ट पता है ललित मोदी को बचाने के लिए उनके सहयोगी मंत्रियों श्रीमति सुषमा स्वराज और श्रीमति वसुंधरा राजे के लगातार झूठ का पर्दाफाश हो गया है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बयानों से मुद्दे को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब प्रधानमंत्री खुद भी प्रत्यार्पण कानूनों की उलझनों के बहाने नहीं बना सकते हैं।

हम प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि वो ललित मोदी को वापस लेकर आएं और सुनिश्चित करें कि संसद का आगामी सत्र सुचारु रूप से चल सके। इस विषय में कोई भी बहाना बनाने का साफ मतलब यही होगा कि मोदी गेट घोटाले में बड़े मोदी, छोटे मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

वन रैंक वन पेंशन

भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा वन रैंक वन पेंशन आंदोलन को आज 151 दिन पूरे हो गए। भूतपूर्व सैनिकों ने आज तक अपने 22000 पदक लौटा दिए हैं और अगले 24 घंटों में अगले 10,000 पदक और लौटाए जाने वाले हैं। रक्षामंत्री श्री मनोहर परिकर ने भारत के भूतपूर्व सैनिकों को 'सैनिकों से अलग' कहकर उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनसे मिलकर उनकी परेशानी सुनने का वक्त तक नहीं मिला। इसके विपरीत भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस ने 14 अगस्त, 2015 को जंतर–मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों को बलपूर्वक हटाकर उनका अपमान करने की कोशिश भी की। लगभग 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों की मांग के लिए मौन रहकर मोदी सरकार उनक तकलीफों को बढ़ा रही है।

7 नवंबर, 2015 को मोदी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद भारत में तीनों सशस्त्र बलों के भूतपूर्व एवं सेवाधीन सैनिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस नोटिफिकेशन की प्रति इस प्रेस विज्ञप्ति के **संलग्नक A-1** में संलग्न है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे :–

1. 7 नवंबर, 2015 को जारी नोटिफिकेशन में तीनों सशस्त्र बलों के लगभग 30 से 40 प्रतिशत सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के फायदों से वंचित कर दिया गया, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन में 'समयपूर्व रिटायरमेंट' लेने वालों को शामिल नहीं किया गया। 7 नवंबर, 2015 के नोटिफिकेशन के चौथे खंड में कहा गया है कि ''4. जो लोग आर्मी रूल 1954 या समतुल्य नेवी या एयरफोर्स रूल्स के नियम 13(3)1(i) (b),13(3)1(iv) या नियम 16B के अंतर्गत **अपने खुद के निवेदन पर** सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें वन रैंक वन पेंशन के फायदे नहीं मिलेंगे।''

   क्या भाजपा सरकार को यह जानकारी नहीं है कि जूनियर रैंक्स खासकर जवानों/जूनियर कमीशंड ऑफिसरों का रिटायरमेंट 40 वर्ष की आयु में हो जाता है? केवल 30 प्रतिशत अधिकारियों का ही कर्नल के रूप में चयन होता है। बचे हुए अधिकांश अधिकारी सेवा के 20 साल पूरे होने पर समयपूर्व रिटायरमेंट ले लेते हैं। समयपूर्व रिटायरमेंट लेने वाले सैनिकों की संख्या भी 30–40 प्रतिशत है। तीनों सशस्त्र बलों के सभी सेवाधीन सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के फायदों से वंचित कर देना उनके साथ अन्याय है। इस निर्णय से सशस्त्र बलों का विभाजन होकर उनके अंदर ही दो अलग अलग श्रेणिया बन जाएंगी, जिनमें एक तो वो सैनिक होंगे, जो 1 जुलाई, 2014 से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्हें वन रैंक वन पेंशन के फायदे मिलेंगे और दूसरी श्रेणी में तीनों सशस्त्र बलों के वो सेवाधीन सैनिक होंगे, जिन्हें वन रैंक, वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। यह न तो तर्कपूर्ण है और न ही न्यायपूर्ण।

   प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों के साथ दीवाली मनाते हैं, लेकिन फिर वो दीवाली पर उन्हीं लोगों को वन रैंक, वन पेंशन के फायदों से वंचित करके उनके साथ अन्याय करते हैं।
2. मोदी सरकार ने हमारे 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों की छः मांगों को क्यों ठुकरा दिया? अपनी पीठ थपथपाने की जगह सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन की घोषणा भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा एक तरफा ठुकराए जाने पर विचार क्यों नहीं किया?
3. वन रैंक, वन पेंशन के क्रियान्वयन के लिए 1 जुलाई, 2014 की शर्त रखने की क्या वजह है? सरकार ने कांग्रेस की पिछली यूपीए सरकार के द्वारा निर्धारित 1 अप्रैल, 2014 से वन रैंक वन पेंशन का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया। मोदी सरकार कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा निर्धारित वन रैंक, वन पेंशन की तारीख को खारिज करके भूतपूर्व सैनिकों को इसके फायदों से वंचित क्यों कर रही है?
4. सरकार ने पांच साल के बाद पेंशन की समीक्षा की शर्त क्यों रखी, जबकि अनुभवी लोग दो साल के बाद इसकी समीक्षा की मांग कर रहे थे।
5. रिटायर्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों की एक पांच सदस्यीय कमेटी की जगह वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय कमेटी की क्या जरूरत थी?
6. कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए वन रैंक वन पेंशन फॉर्मूला में हमारे भूतपूर्व सैनिकों को 'सर्वाधिक वेतन' के आधार पर पेंशन दी जानी थी। वर्तमान फॉर्मूले में पेंशन 'सबसे कम और

सबसे अधिक वेतन' के औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मोदी सरकार इस पक्षपाती फॉर्मूले के द्वारा हमारे भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन के फायदों से वंचित क्यों कर रही है, जिसके कारण विभिन्न पेंशनभोगियों की पेंशन में असमानता पैदा हो जाएगी?

7. भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने वन रैंक वन पेंशन के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा 500 करोड़ रु. की पूंजी आबंटित करने को 'मजाक' कहकर सैनिकों का अपमान किया है। क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि भाजपा के वित्त मंत्री और रक्षामंत्री ने 10 जुलाई, 2014 को पूरे 2014–15 वित्त वर्ष के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए मात्र 1000 करोड़ रु. ही आबंटित किए? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि भाजपा का बजट भाषण भूतपूर्व सैनिकों को अपमानित करने के लिए एक मजाक था?
8. भाजपा सरकार ने वित्तवर्ष 2014–15 में रक्षा बजट का केवल 87.2 प्रतिशत ही खर्च किया। 2,29,000 करोड़ रु. के रक्षा बजट के मुकाबले मोदी सरकार केवल 1,93,923 करोड़ रु. ही खर्च कर सकी और लगभग 25,077 करोड़ रु. बेकार पड़े रहे। क्या इस पैसे का प्रयोग वन रैंक, वन पेंशन के लिए नहीं किया जा सकता था? क्या यह रकम वन रैंक, वन पेंशन के क्रियान्वयन में भाजपा की अनिच्छा के कारण बची नहीं रही?

कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा और प्रधानमंत्री इस विषय में अपनी सफाई दें, आन्दोलनकारी भूतपूर्व सैनिकों से मिलें और तीनों सशस्त्र बलों के सेवाधीन सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन से वंचित करने के लिए बनाए गए कृत्रिम विभाजन को समाप्त करे।

रणदीप सिंह सुरजेवाला